गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 281
दि. 12.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत बंद का आह्वान, सेवाओं पर असर संभव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी, बुधवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते भारत बंद का निर्णय लिया गया है। इस बंद के कारण कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं, सरकारी कार्यालय, परिवहन और बाजार प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ स्थानों पर स्कूल और कॉलेजों के संचालन पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

ट्रेड यूनियनों का मुख्य विरोध पिछले वर्ष 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किए गए चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लेकर है। संगठनों का आरोप है कि नए लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, नौकरी की सुरक्षा घटाते हैं और नियोक्ताओं को नियुक्ति तथा छंटनी में अधिक छूट देते हैं। इसलिए वे इन संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यूनियनों ने निजीकरण की नीतियों, वेतन संबंधी मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा में कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए व्यापक पुनर्विचार आवश्यक है।

प्रमुख मांगों में चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना, बीज विधेयक के मसौदे और विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेना, तथा कुछ अन्य प्रस्तावित नीतियों पर पुनर्विचार शामिल है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को सशक्त बनाने और उसका बजट बढ़ाने की मांग की गई है। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है ताकि आर्थिक असमानता कम हो सके। पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी इस बंद का एक प्रमुख मुद्दा है। कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना के स्थान पर

पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पुरानी व्यवस्था कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 का भी कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, और इसे वापस लेने की मांग उठाई गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) जैसे किसान संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। संगठनों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में हड़ताल के नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बंद को सफल बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। हालांकि, बंद का असर अलग-अलग राज्यों में स्थानीय समर्थन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

स्कूल और कॉलेजों को लेकर देशव्यापी स्तर पर बंद की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी, केरल, कर्नाटक और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में शिक्षण संस्थानों के प्रभावित होने की संभावना जताई गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं या स्थानीय संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित स्कूलों और कॉलेजों की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।

बैंकिंग सेवाओं पर आंशिक प्रभाव पड़ सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसे प्रमुख संगठनों ने अपने सदस्यों से हड़ताल में भाग लेने का आग्रह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को सूचित किया है कि 12 फरवरी को सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकों की ओर से उस दिन को आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है, इसलिए शाखाएं खुली रह सकती हैं, लेकिन कार्य प्रभावित हो सकता है। ग्राहकों को चेक क्लियरेंस, जमा-निकासी और शाखा सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहने की संभावना है, हालांकि मामूली व्यवधान संभव है। निजी बैंकों की सेवाएं स्थान विशेष के अनुसार अलग-अलग रह सकती हैं।

बाजारों और परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन, सड़क अवरोध या चक्का जाम की स्थिति बन सकती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन बाधित हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में बाजार और दुकानें बंद रह सकती हैं। कई राज्यों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रह सकती है या कार्यालय आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं।

आपातकालीन सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य रूप से कार्य करती रहने की संभावना है। हवाई अड्डों और अन्य आवश्यक सेवाओं के भी संचालित रहने की उम्मीद है, हालांकि यातायात बाधित होने की स्थिति में यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, भारत बंद का असर क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों, स्थानीय संगठनों की भागीदारी और प्रशासनिक प्रबंधन पर निर्भर करेगा। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा या बैंकिंग से संबंधित कार्यों की योजना बनाते समय स्थानीय प्रशासन और संबंधित संस्थानों की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें तथा आवश्यक सावधानियां बरतें।

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फेरबदल के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वे उन सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला करें, जो पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही जिले या पद पर कार्यरत हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयोग के निर्देशों के अनुसार यह आदेश जिला स्तर के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसमें जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ), ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) जैसे पद शामिल हैं। ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मतदाता सूची के अद्यतन से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा समन्वय और मतगणना तक कई अहम जिम्मेदारियां इन्हीं के अधीन होती हैं। आयोग का मानना है कि यदि ऐसे अधिकारी लंबे समय तक एक

ही जिले में तैनात रहते हैं, तो स्थानीय स्तर पर उनके प्रशासनिक या व्यक्तिगत संबंध विकसित हो सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

पुलिस विभाग में भी व्यापक बदलाव किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, अतिरिक्त एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो जिले या रेंज स्तर पर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील विषय होती है। ऐसे में आयोग चाहता है कि सुरक्षा तंत्र पूरी तरह तटस्थ और स्वतंत्र ढंग से कार्य करे। लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से उत्पन्न संभावित प्रभावों को समाप्त करने के लिए यह स्थानांतरण आवश्यक माना गया है।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया कोई असाधारण कदम नहीं है, बल्कि हर बड़े चुनाव से पहले अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। आयोग का उद्देश्य किसी विशेष अधिकारी या राज्य सरकार पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले और मतदाता बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

आयोग ने एक अतिरिक्त दिशा-निर्देश भी जारी किया है, जिसके तहत वे अधिकारी जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी जिले में जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर या पुलिस निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था, उन्हें इस बार उसी जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। आयोग का तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता के साथ-साथ निष्पक्षता भी आवश्यक है। यदि वही अधिकारी दोबारा उसी जिले में जिम्मेदारी संभालते हैं, तो निष्पक्षता की धारणा प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस बार नई तैनाती के माध्यम से प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, सूत्रों के अनुसार राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को इस स्थानांतरण निर्देश से छूट दी गई है। इसका कारण यह है कि मुख्यालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी सीधे तौर पर जिला स्तर की चुनावी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। फिर भी, यदि आवश्यकता पड़ी तो आयोग आगे और निर्देश जारी कर सकता है।

चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इन निर्देशों के त्वरित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राज्य सरकार को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्थानांतरण सूची तैयार कर आयोग को सौंपनी होती है। इसके बाद आयोग अंतिम स्वीकृति देता है। यदि किसी अधिकारी के स्थानांतरण में देरी होती है या निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह आवश्यक कार्रवाई कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में यह कदम विशेष महत्व रखता है। पिछले चुनावों के दौरान कई जिलों में प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर विवाद सामने आए थे। ऐसे में इस बार आयोग पहले से ही सतर्क दिखाई दे रहा है। व्यापक स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण से चुनावी माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और राजनीतिक दलों के बीच भरोसा बढ़ सकता है।

सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का पक्ष स्पष्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रखे गए प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि वांगचुक को चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है और उन्हें किसी गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जेल नियमावली के तहत वांगचुक की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी 28 बार चिकित्सकीय जांच हो चुकी है और हर बार उनकी स्थिति संतोषजनक पाई गई है। मेहता ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पाचन संबंधी हल्की समस्या हुई थी, जिसके लिए आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक पूरी तरह फिट और तंदुरुस्त हैं, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर उनकी रिहाई का कोई औचित्य नहीं बनता। केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत की गई हिरासत एक गंभीर और संवेदनशील विषय है, जिसमें ढील देने से कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत का उद्देश्य संभावित खतरों को रोकना है, और ऐसे मामलों में नियमों के तहत ही निर्णय लिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल चिकित्सा आधार का हवाला देकर हिरासत समाप्त करना संभव नहीं है, जब तक कि गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति न हो।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने भी केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि वांगचुक की गतिविधियों और बयानों ने कुछ स्थानों पर उग्र विरोध प्रदर्शनों को प्रेरित किया। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक ने नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों के उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हालांकि, इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि क्या वांगचुक ने प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का समर्थन किया था या यह केवल युवाओं के दृष्टिकोण का उल्लेख था।

पीठ ने केंद्र से कहा कि यदि वांगचुक ने किसी संदर्भ में युवाओं के विचारों का जिक्र किया है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह उनके व्यक्तिगत विचार नहीं थे और उन्होंने हिंसक तरीकों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने इस बिंदु पर स्पष्टता की आवश्यकता जताई, ताकि यह समझा जा सके कि कथित बयान किस संदर्भ में दिए गए थे। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

यह मामला वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में दावा किया गया है कि वांगचुक की हिरासत अनुचित है और उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वांगचुक एक शांतिपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनकी गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही हैं। उनकी हिरासत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देखा जा रहा है।

सोनम वांगचुक देश-विदेश में अपने नवाचारों और पर्यावरणीय अभियानों के लिए जाने जाते हैं। लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा सुधार और जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों की व्यापक सराहना हुई है। ऐसे में उनकी हिरासत ने कई सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों को चिंतित किया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह कार्रवाई आवश्यक थी।

एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को बिना मुकदमे के एक निश्चित अवधि तक रखा जा सकता है, यदि यह माना जाए कि उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती हैं। इस कानून को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में कहा है कि निवारक हिरासत का उपयोग अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह सभी तथ्यों और दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करेगी। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह वांगचुक के कथित बयानों और गतिविधियों के संदर्भ में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे, ताकि यह तय किया जा सके कि हिरासत उचित है या नहीं। अदालत ने संकेत दिया कि वह इस मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय देगी। इस मामले ने व्यापक स्तर पर बहस छेड़ दी है कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलनों और विचारों की अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाना उचित है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि यदि किसी बयान या गतिविधि से सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, तो प्रशासन को निवारक कदम उठाने का अधिकार है। अदालत के अंतिम निर्णय पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला आने वाले दिनों में संवैधानिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

आपके बैंक से केवाईसी अपडेट का अलर्ट आया है?
कोई बात नहीं - केवाईसी को अप-टू-डेट रखने से आपको बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी बिना रुकावट के।

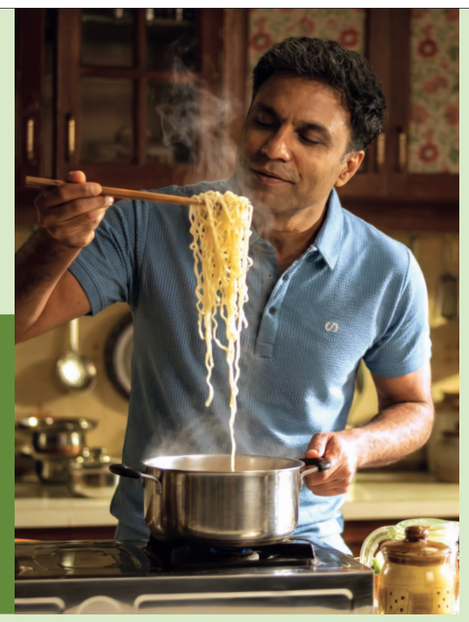

आपका केवाईसी अपडेट करना है नूडल्स बनाने जितना आसान!

कैसे?

अगर 'केवाईसी में कोई बदलाव नहीं है' या 'सिर्फ पते में बदलाव हुआ है' तो एक सेल्फ-डिक्लरेशन देकर इसे अपडेट किया जा सकता है।

- पंजीकृत ईमेल/ मोबाइल नंबर
- ऑनलाइन बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग
- एटीएम
- बैंक के कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)
- पत्र, आदि।

केवाईसी जानकारी में अन्य बदलाव इनकी मदद से करें:

- आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी
- वीडियो केवाईसी (जहाँ उपलब्ध हो)

या

आपका अपडेट किया हुआ **ऑफ़िशियली वैलिड डॉक्युमेंट (ओवीडी)*** बैंक की शाखा में जमा करके।

*ओवीडी: पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/आधार कार्ड/ नरेगा जॉब कार्ड/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी पत्र

केवाईसी अब कराई जा सकती है जल्दी और आसानी से
बैंक द्वारा अधिकृत माध्यमों से ही केवाईसी अपडेट कराएं।

क्या आप जानते हैं? एक बैंक में अपडेट की गई केवाईसी आपके अन्य सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अपडेट हो जाती है, सीकेवाईसीआर के ज़रिए।

क्यूआर कोड स्कैन करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें https://rbikehtahai.rbi.org.in
अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर भेजें।
आधिकारिक व्हॉट्सऐप नं. 99990 41935 / 99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संपादकीय

साइबर डकैती पर सख्ती

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रॉड सीधे-सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है। इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले-भाले लोगों को जिस तरह साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

कृषि उपज के लिए बाजार को खोलना यानी बवंडर को निमंत्रण

> “ भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी।

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे। भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है।

रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती-किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है।

किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा।

भारत-अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनीं पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को 'रेड-लाइन' यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। इस बवंडर का सामना करने की हिम्मत विरली राजनीतिक ताकतें ही कर सकती हैं। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए तीन लाख अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो निर्यात बढ़ेगा, उससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथनॉल, तंबाकू, सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा। दोनों देश अपने-अपने हित वाले क्षेत्रों में एक-दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी-बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा।

प्रेरणा

सच्ची प्रतिष्ठा ज्ञान, धैर्य और कर्म से मिलती है

प्राचीन चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अपने संतुलित विचारों, नैतिक शिक्षाओं और व्यावहारिक ज्ञान के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। वे मानते थे कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पद या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि उसके आचरण, ज्ञान और निरंतर कर्म से तय होता है। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ नगर की गलियों से होकर गुजर रहे थे। वातावरण शांत था, लोग अपने-अपने कार्यों में व्यस्त थे, पर उसी भीड़ के बीच झील के किनारे एक युवक अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और हताशा स्पष्ट झलक रही थी। वह बार-बार अपने हाथों से मिट्टी को कुरेद रहा था, जैसे अपने भीतर के असंतोष को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हो।

कन्फ्यूशियस ने उसे देखा और उसके पास जाकर शांत स्वर में पूछा, "पुत्र, तुम्हारे मन में इतना क्लेश क्यों है?" युवक ने भारी आवाज में उत्तर दिया, "गुरुदेव, मैं एक छोटे पद पर कार्य करता हूं। मैं परिश्रम करता हूं, अपने दायित्व पूरे करता हूं, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरे सुझावों का उपहास होता है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें, मेरी बातों को महत्व दें, पर मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव होगा।" उसकी आंखों में पीड़ा थी, जैसे वह अपने अस्तित्व को ही प्रश्नों के घेरे में देख रहा हो।

कन्फ्यूशियस कुछ क्षण मौन रहे। फिर वे जमीन पर बैठ गए और पास पड़ी एक लकड़ी से मिट्टी पर एक बड़ा वृत्त खींचा। उन्होंने युवक से कहा, "इसे ध्यान से देखो। यह वृत्त समाज है—विशाल, विस्तृत और अनेक स्वभावों से भरा हुआ।" फिर उन्होंने उस वृत्त के मध्य एक छोटा-सा बिंदु बनाया और बोले, "यह तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, इसलिए महत्वहीन हो। पर छोटा होना कभी भी व्यर्थ होना नहीं होता।"

युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कन्फ्यूशियस ने उस बिंदु से बाहर की ओर कई रेखाएं खींचीं, जो वृत्त की सीमा तक पहुंच रही थीं। वे बोले, "जब यह बिंदु केवल बिंदु बना रहता है, तब इसकी पहचान सीमित होती है। पर जब इससे रेखाएं बाहर की ओर फैलती हैं, तब यह पूरे वृत्त को छू लेता है। उसी प्रकार जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा कर्म बाहर की ओर विस्तार पाता है, तब समाज स्वयं तुम्हें पहचानने लगता है।"

युवक ने धीरे से पूछा, "पर मैं क्या करूं? लोग तो पहले से ही मुझे कम आंकते हैं।" कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराते हुए कहा, "सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। यदि कोई सम्मान मांगता है, तो वह क्षणिक होता है। सच्चा सम्मान अर्जित किया जाता है, और वह समय के साथ स्थायी बनता है। यदि तुम अपने भीतर गुणों का विकास करोगे, तो लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "अक्सर हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रक्रिया को भूल जाते हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुनें, पर क्या तुमने अपने ज्ञान को इतना गहरा बनाया है कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हों? क्या तुम्हारा आचरण इतना संतुलित है कि लोग तुम्हें विश्वसनीय मानें? क्या तुम्हारा व्यवहार इतना विनम्र है कि लोग तुम्हारे पास सहज आ सकें?" युवक चुप था, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर उसके भीतर ही छिपे थे।

कन्फ्यूशियस ने उदाहरण देते हुए कहा, "जल को देखो। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं चट्टान को काटूंगा। वह बस निरंतर बहता रहता है। उसकी निरंतरता ही अंततः कठोर पत्थर को भी आकार दे देती है। यदि तुम भी निरंतर सीखते रहोगे, अपने कर्म को सुधारते रहोगे और धैर्य बनाए रखोगे, तो समय तुम्हारे पक्ष में होगा।"

युवक ने स्वीकार किया कि वह अक्सर आलोचना से आहत हो जाता है और भीतर ही भीतर क्रोधित भी हो जाता है। कन्फ्यूशियस ने समझाया, "क्रोध और हताशा तुम्हारे बिंदु को और छोटा कर देते हैं। यदि तुम भीतर से संतुलित रहोगे, तो बाहरी उपहास तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। आत्मसम्मान का आधार दूसरों की स्वीकृति नहीं, बल्कि स्वयं की सच्चाई होती है।" उन्होंने यह भी कहा कि केवल अपने काम तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। समाज में स्थान पाने के लिए व्यक्ति को दूसरों की सहायता, सहयोग और संवेदनशीलता का परिचय देना होता है। जब तुम केवल अपने दायित्व नहीं, बल्कि दूसरों की कठिनाइयों को भी समझोगे, तब लोग तुम्हें एक अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। सम्मान केवल दक्षता से नहीं, बल्कि उदारता और सहयोग से भी मिलता है।

युवक के चेहरे पर अब विचारों की गहराई दिखाई देने लगी थी। उसने पूछा, "क्या यह मार्ग कठिन नहीं होगा?" कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, "हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि वह अधीर होकर मिट्टी को दोष देने लगे, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। जब जड़ें गहरी होंगी, तब शाखाएं स्वयं फैलेंगी।"

धीरे-धीरे युवक के भीतर आशा का संचार होने लगा। उसे समझ में आ गया कि सम्मान कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसी छवि है जो निरंतर प्रयास, संयम और आत्मविकास से निर्मित होती है। उसने प्रणाम करते हुए कहा, "गुरुदेव, मैं अब सम्मान की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैं स्वयं को योग्य बनाऊंगा, ताकि लोग मुझे पहचानें।"

कन्फ्यूशियस ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, "याद रखो, पहले अपने भीतर आकार लो, फिर संसार तुम्हें स्थान देगा। जब तुम्हारा ज्ञान प्रकाश बनेगा, तो वही प्रकाश दूसरों तक पहुंचेगा और तुम्हारी पहचान बनेगा।"

झील के किनारे हुई यह छोटी-सी बातचीत एक गहरी शिक्षा बन गई। जीवन में प्रतिष्ठा पाने का मार्ग बाहर से भीतर नहीं, बल्कि भीतर से बाहर की ओर जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को परिष्कृत करता है, अपने कर्म को निरंतर बनाता है और अपने व्यवहार को संतुलित रखता है, तब समाज उसे अनदेखा नहीं कर सकता। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि स्वयं को विकसित करने से मिलता है। जो व्यक्ति अपने भीतर विस्तार करता है, वही समाज के विशाल वृत्त को स्पर्श कर पाता है और अंततः सच्ची प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है।

प्रकृति रक्षा के लिए कड़े कानूनी बदलावों की जरूरत

मानवता ने अपनी प्रगति की गाथा अक्सर प्रकृति की कीमत पर लिखी है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, हमने विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के ढेर तो खड़े कर लिए, लेकिन इसकी वजह से नदियों को विषाक्त नालों और हरे-भरे जंगलों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। आज जब हिमालय की नींव धंस रही है और हवा सांसों में जहर घोल रही है, तब एक तीखा सवाल सामने है - क्या अपराध इंसानों के खिलाफ ही 'संगीन' होते हैं?

इसी सवाल से एक क्रांतिकारी शब्द ने जन्म लिया - 'ईकोसाइड' यानी 'प्रकृति का नरसंहार'। जिस प्रकार विश्व ने 'जेनोसाइड' को मानवता के विरुद्ध वीभत्स अपराध मानकर दंडित किया, अब प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे इस व्यवस्थित विनाश को भी उसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी श्रेणी में रखा जाए। अब न्याय केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगलों और नदियों के लिए भी होना चाहिए, जिनका अस्तित्व हमारी लालसा की भेंट चढ़ गया। वर्तमान परिदृश्य में 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे' का सिद्धांत अपनी सार्थकता खोकर केवल 'वैध व्यापारिक लागत' बनकर रह गया है। बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने पर्यावरण विनाश से भारी मुनाफा कमाते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को अपनी बैलेंस शीट में मामूली खर्च मानकर चुका देते हैं। इस व्यवस्था ने पैसे को संरक्षण के बजाय विनाश का 'लाइसेंस' बना दिया है। ईकोसाइड की अवधारणा इसी खामी पर प्रहार करते हुए नागरिक दायित्व को 'कठोर आपराधिक उत्तरदायित्व' में बदलने की वकालत करती है। संदेश देती है कि प्रकृति कोई 'कमोडिटी' नहीं जिसे नष्ट करके उसकी कीमत चंद रुपयों में चुकाई जा सके; बल्कि जीवंत इकाई है।

जब भोपाल गैस त्रासदी और श्रीराम फर्टिलाइजर्स जैसी भयावह घटनाएं हुईं, तो न्यायपालिका ने कानून की सीमाओं को विस्तार दिया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) के मामले में 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण दायित्व) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पष्ट किया कि यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक गतिविधि में लगा है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है, तो वह उद्योग बिना अपवाद उत्तरदायी होगा। ईकोसाइड कानून इसी 'पूर्ण दायित्व' के विचार को अगले स्तर पर ले जाता है। यह केवल क्षतिपूर्ति की बात नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही और जेल की सजा का प्रावधान करता है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों में कानून का भय और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा हो। कानूनी रूपांतरण का वह चरण जहां पर्यावरण का विनाश मानवता के खिलाफ संगीन जुर्म माना जाएगा।

इस कानूनी विमर्श का मुख्य केंद्र 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण से हटकर 'प्रकृति-केंद्रित' न्यायशास्त्र को अपनाना है। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 51ए(जी) और 21) पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य और अधिकार मानता है। लेकिन अब समय है प्रकृति के 'स्वतंत्र अधिकारों' को मान्यता देने का। ए. नागराजा (2014) और सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017) जैसे मामलों ने जानवरों और नदियों (गंगा-यमुना) को 'विधिक व्यक्ति' का दर्जा देकर नई राह दिखाई है। यदि एक नदी कानून की नजर में 'व्यक्ति' है, तो उसे प्रदूषित करना 'हत्या के प्रयास' जैसा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर ईकोसाइड को अपराध घोषित करने की मुहिम तेज हो रही है, जहां बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों ने अपने घरेलू कानूनों में इसे शामिल कर मिसाल पेश की है। वर्तमान में 'स्टॉप ईकोसाइड इंटरनेशनल' जैसे संगठन यह प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की 'रोम संविधि' में संशोधन कर ईकोसाइड को नरसंहार और युद्ध अपराधों की श्रेणी में 'पांचवां अंतर्राष्ट्रीय अपराध' घोषित किया जाए। ताकि कोई राष्ट्र या कॉर्पोरेट विकास की आड़ में पर्यावरण को अपूरणीय क्षति न पहुंचा सके।

भारत के लिए ईकोसाइड कानून अपनाना केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' के दर्शन को मानने वाले देश के लिए प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करना एक स्वाभाविक कदम है। यह कानून विकास का विरोधी नहीं, बल्कि 'जिम्मेदार और सतत विकास' का समर्थक है। यह संतुलित प्रगति की परिभाषा है जहां मानवता और प्रकृति सह-अस्तित्व में फलें-फूलें।

निश्चित रूप से, ईकोसाइड कानून के मार्ग में 'गंभीर क्षति' को परिभाषित करने और साक्ष्य जुटाने जैसी चुनौतियां हैं। इसके समाधान के लिए हमें अपने कानूनी शिक्षण में 'अर्थ ज्यूरिसप्रुडेंस' को शामिल करना होगा। अब हम जोशीमठ जैसे संकटों या दम तोड़ती नदियों को केवल 'प्राकृतिक आपदा' का लेबल न दें, बल्कि उन मानवीय निर्णयों की आपराधिक जांच करें जिन्होंने इन आपदाओं का मार्ग प्रशस्त किया। हमें एक ऐसी उत्तरदायी व्यवस्था चाहिए जो विकास की आड़ में किए गए संस्थागत अपराधों को पहचानकर उन्हें दंडित कर सके।

ईकोसाइड केवल एक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी है। प्रकृति को 'वस्तु' मानने की हमारी भूल हमें विनाश की ओर ले जा रही है। जब तक कानून की किताबों में 'प्रकृति की हत्या' को 'मानव की हत्या' के समकक्ष गंभीरता नहीं दी जाएगी, तब तक विनाश का यह सिलसिला नहीं थमेगा। ईकोसाइड कानून को मान्यता देना इस धरती के प्रति हमारी जवाबदेही का प्रमाण होगा।

अभियान

ऑनलाइन आरती में झलकती बाबा कालभैरव की दिव्य कृपा

सनातन धर्म की अविचल धारा में बाबा कालभैरव का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक माना जाता है। वे भगवान शिव के रौद्र, जाग्रत और करुणामय रूप हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, समय का स्वामी माना जाता है और धर्म की मर्यादा के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी आराधना से भय दूर होता है, बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में साहस तथा स्थिरता का संचार होता है। युग बदलते रहे, साधन बदलते रहे, पर भक्ति की भावना कभी नहीं बदली। आज जब संसार डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, तब बाबा कालभैरव का दरबार भी आधुनिक माध्यमों के द्वारा भक्तों के और अधिक समीप आ गया है। कभी ऐसा समय था जब दूर-दराज के भक्त केवल मन ही मन बाबा का स्मरण कर संतोष कर लेते थे, क्योंकि मंदिर तक पहुंच पाना संभव नहीं होता था। वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आर्थिक सीमाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां या विदेश में निवास—ये सभी कारण किसी भक्त को मंदिर दर्शन से वंचित कर सकते हैं। परंतु अब तकनीक ने उस दूरी को मिटा दिया है। ऑनलाइन विशेष पूजा और लाइव दिव्य आरती की सुविधा ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो भगवान तक पहुंचने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब कोई भक्त अपने घर में बैठकर कालभैरव मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाता है और विशेष पूजा का विकल्प चुनता है, तो वह केवल एक डिजिटल प्रक्रिया नहीं अपनाता, बल्कि अपने हृदय की श्रद्धा को एक संकल्प के रूप में व्यक्त करता है। पंजीकरण की सरल प्रक्रिया के माध्यम से वह अपना नाम, गोत्र और पूजा का उद्देश्य दर्ज करता है। यह वही प्राचीन परंपरा है, जिसमें पंडित मंत्रोच्चार करते समय भक्त का नाम और गोत्र उच्चारित करते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले भक्त मंदिर प्रांगण में खड़ा होता था और अब वह अपने घर के पूजा कक्ष में दीपक जलाकर बैठा होता है।

निर्धारित समय पर जब लाइव आरती का प्रसारण आरंभ होता है, तो स्क्रीन पर मंदिर का दृश्य दिखाई देता है। दीपों की पंक्तियां, धूप और चंदन की सुगंध, घंटों की गूंज, शंखनाद और "हर हर महादेव" का जयघोष वातावरण को दिव्य बना देता है। भक्त हाथ जोड़कर स्क्रीन के सामने बैठता है और अनुभव करता है कि वह स्वयं बाबा के दरबार में उपस्थित है। उस क्षण घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र हो उठता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि लाइव आरती के समय उनकी आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं और मन में गहरी शांति उतर आती है। कालभैरव की आराधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है जो जीवन में भय, न्यायिक समस्याओं, शत्रु बाधा या ग्रहदोष से पीड़ित हों। शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने में बाबा की कृपा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। कालाष्टमी और भैरव अष्टमी के दिन तो विशेष महत्त्व रखते हैं। इन पावन तिथियों पर ऑनलाइन पूजा बुक करने वाले भक्तों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों की गई आराधना शीघ्र फल देती है।

ऑनलाइन पूजा के दौरान पंडित जी विधिपूर्वक मंत्रोच्चार करते हैं, हवन और अर्चना संपन्न करते हैं तथा भक्त के नाम से संकल्प लेकर बाबा के चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। यह जानकर भक्त का हृदय भावविभोर हो उठता है कि उसकी कामना, उसका दुख और उसकी आशा सीधे बाबा तक पहुंच रही है। जब पंडित जी उच्च स्वर में उसका नाम और गोत्र बोलते हैं, तो उसे अनुभव होता है कि उसकी उपस्थिति भले ही शारीरिक रूप से न हो, पर उसकी आत्मा उस क्षण मंदिर में उपस्थित है। पूजा के पश्चात मंदिर की ओर से प्रसाद भक्त के पते पर भेजा जाता है। जब वह प्रसाद घर पहुंचता है, तो परिवार के लिए वह अत्यंत पवित्र क्षण होता है। प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो बाबा का आशीर्वाद स्वयं घर की चौखट पर आया हो। यह केवल मिठाई या पूजन सामग्री नहीं, बल्कि कृपा और विश्वास का प्रतीक होता है।

ऑनलाइन विशेष पूजा के लिए सामान्यतः 500 से 2,000 रुपये तक का शुल्क निर्धारित है। इसमें पूजा सामग्री, पंडित जी की दक्षिणा, लाइव प्रसारण और प्रसाद की व्यवस्था सम्मिलित रहती है। भुगतान सुरक्षित डिजिटल माध्यम से किया जाता है और पुष्टि के रूप में रसीद तथा बुकिंग आईडी प्राप्त होती है। यह पारदर्शिता भक्तों के विश्वास को और भी दृढ़ करती है।

कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या डिजिटल माध्यम से की गई पूजा उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी मंदिर जाकर की गई पूजा। इस विषय में संतों का मत स्पष्ट है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हृदय से होकर जाता है। यदि भावना निर्मल हो और श्रद्धा अटूट हो, तो स्थान और माध्यम का महत्व गौण हो जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। यदि भक्त अपने घर में बैठकर पूर्ण श्रद्धा से मंत्र सुनता है, आरती में सम्मिलित होता है और बाबा का स्मरण करता है, तो उसे वही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जो मंदिर में उपस्थित होकर होता है।

डिजिटल दरबार की यह व्यवस्था विशेष रूप से उन भक्तों के लिए वरदान है जो विदेशों में रहते हैं। वे समय के अंतर के बावजूद अपने सुविधानुसार पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। तकनीक ने भक्ति को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। अब न दूरी बाधा है, न समय। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है।

फिर भी यह आवश्यक है कि भक्त केवल आधिकारिक और विश्वसनीय माध्यमों का उपयोग करें, ताकि उनकी श्रद्धा सुरक्षित रहे। सजगता और विश्वास दोनों का संतुलन आवश्यक है। डिजिटल सुविधा का उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं, बल्कि आस्था को सशक्त बनाना है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि बाबा कालभैरव का यह डिजिटल दरबार परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। जहां एक ओर सदियों पुरानी वैदिक विधियां और मंत्रोच्चार हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक है, जिसने इस दिव्य अनुभव को हर घर तक पहुंचा दिया है। भक्ति का सार भाव में है। यदि मन सच्चा है और विश्वास दृढ़ है, तो बाबा की कृपा हर माध्यम से प्राप्त होती है। घर बैठे की गई आरती भी उतनी ही पवित्र है जितनी मंदिर में खड़े होकर की गई प्रार्थना। बाबा कालभैरव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, चाहे वह काशी के प्रांगण से उठे या किसी दूर देश के छोटे से घर से। यही इस युग की सबसे सुंदर भक्ति है, जहां तकनीक ने आस्था को और अधिक व्यापक, सुलभ और जीवंत बना दिया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देने वाले 'अमूल एआई' का लोकार्पण किया

▸▸ गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा अन्य मंत्रियों की विशेष उपस्थिति

▸▸ 'अमूल एआई' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बनाने का माइलस्टोन बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देने वाले 'अमूल एआई' का बुधवार को लोकार्पण करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह 'अमूल एआई' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बनाने का माइलस्टोन बनेगा। आणंद में बुधवार को राज्य के 18,500 से अधिक गाँवों में 36 लाख दूध उत्पादकों की सहकारी संस्था, विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था तथा डेयरी ब्रैंड के रूप में ख्याति प्राप्त अमूल द्वारा किसान से टेक्नोलॉजी तक सहकारिता को स्मार्ट बनाने वाली नवीन 'अमूल एआई' क्रांति का शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष तथा बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी, वित्त राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल और गुजरात राज्य दुग्ध विपणन परिसंघ (जीएसएमएमएफ) के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में 'अमूल एआई' का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पिछले 11 वर्षों में देश की आर्थिक विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ी है, जिसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस संदर्भ में उन्होंने डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन की सफलता का उदाहरण देते हुए जोड़ा कि जब प्रधानमंत्री ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन की शुरुआत कराई, तब सबके मन में सवाल था कि यह किस प्रकार सफल होगा ? आज भारत यूपीआई ट्रांजेक्शन में अग्रसर बन गया है और छोटे से छोटे व्यापारी, सब्जी के ठेले, चाय की टपरी तक के छोटे लोग भी डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग करने लगे हैं। यह इसकी विशिष्ट सफलता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 21वीं शताब्दी के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी युग में एआई आधारित विकास के लिए अनेक पहलें की गईं होने का विशेष उल्लेख करते हुए जोड़ा कि सरकार, सहकार तथा टेक्नोलॉजी की त्रिवेणी से आधुनिक विकास की गति अनेक गुना बढ़ गई है। इसे अब एआई और सुदृढ़ बनाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा छोटे व्यक्तियों, ग्रामीण किसानों तथा पशुपालकों के हितों का विचार कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का ही ध्येय रखा है। उनके नेतृत्व में तीन कर्तव्यों पर आधारित इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में भी दूध उत्पादकों के हितों को केन्द्र में रखकर अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; केन्द्रीय बजट में डेयरी इको सिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से 20 हजार वेटरनरी प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए विशेष फंड का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमूल ने अपने सभासदों तथा दूध उत्पादकों को अधिक आय मिले; ऐसी नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल क्रांति से किया है। अमूल अपने सुविकसित विशिष्ट आईटी सिस्टम में पशुपालकों, दूध उत्पादकों तथा सभासदों का जो डेटाबेस है, उसे एकीकृत कर अब 'अमूल एआई' से एडवांटेज इंडिया के लिए सज्ज हुआ है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से हाल ही में अमेरिका तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुई ट्रेड डील डेयरी क्षेत्र के लिए लाभदायी होगी। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से भूमिका देते हुए कहा कि इस डील में डेयरी उत्पादों के निर्यात को बाहर रखने के प्रधानमंत्री के विशिष्ट निर्णय से देश में दूध उत्पादन पर निर्भर 10 करोड़ से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों का जीवन निर्वाह सुरक्षित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास दर्शाया कि इस स्वागत योग्य ट्रेड डील के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश का डेयरी सेक्टर दूध उत्पादन बढ़ाकर विश्व की डेयरी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने विकसित भारत@2047 के लिए स्वदेशी व आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी से ग्लोबल सॉल्यूशन देने की दिशा में 'अमूल एआई' को ठोस कदम बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन आगामी समय में इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स बनेंगे; जिसमें ग्रामीण, कृषि, पशुपालन तथा दूध उत्पादन के साथ सहकारिता क्षेत्र लीड लेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- ▸▸ सरकार, सहकार तथा टेक्नोलॉजी की त्रिवेणी से आधुनिक विकास की गति अनेक गुना बढ़ी है
- ▸▸ तीन कर्तव्यों पर आधारित इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में दूध उत्पादकों के हितों को केन्द्र में रखकर अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं
- ▸▸ केन्द्रीय बजट में डेयरी इको सिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 20 हजार वेटरनरी प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए विशेष फंड का प्रावधान
- ▸▸ वैश्विक ट्रेड डील से देश के डेयरी सेक्टर को लाभ, भारत विश्व की डेयरी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा

इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष तथा बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आणंद की भूमि श्वेत क्रांति के प्रणेता त्रिभोवनदास पटेल की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही है और डॉ. कुरियन की भी कर्मभूमि रही है। आज हजारों पशुपालकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो हम सबके लिए गौरव का क्षण है।

अमूल द्वारा लॉन्च किए गए नए 'सरला' (Sarala) ऐप को एक बड़ी क्रांति बताते हुए उन्होंने कहा कि अमूल ने विश्व में पहली बार दूध के फैट, ठोस रहित वसा (सॉलिड-नॉट-फैट-एसएनएफ) तथा दैनिक हिसाब मोबाइल ऐप पर देने की व्यवस्था की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार का भाव व्यक्त करते हुए श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों द्वारा भारत में दूध एवं डेयरी उत्पाद प्रवेश कराने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा था। यदि बाहर का दूध भारत में आता; तो देश के करोड़ों पशुपालक प्रभावित होते, परंतु प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विरुद्ध चट्टान बनकर खड़े रहते हुए भारतीय पशुपालकों के हितों की रक्षा की है और दूध को मुक्त व्यापार समझौतों (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स-एफटीए) से बाहर रखा है।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने इस घटना को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के लिए जो विशेष प्रयास किए हैं, उनके परिणामस्वरूप ही आज गुजरात इस क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ पार कर रहा है। उन्होंने जोड़ा कि अमूल का यह एआई एप्लिकेशन विश्व का सबसे बड़ा एप्लिकेशन बनने जा रहा है, जो डिजिटल युग में गुजरात की एक अनूठी उपलब्धि है। जिस तरह लोगों ने यूपीआई तथा स्मार्टफोन को अपनाया है, उसी तरह यह एआई टेक्नोलॉजी भी पशुपालकों के जीवन का हिस्सा बनेगी।

सहकारिता क्षेत्र की चर्चा करते हुए श्री वाघाणी ने कहा कि पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि ग्रामीण समृद्धि का आधारस्तंभ है। प्रधानमंत्री ने पृथक सहकारिता मंत्रालय बनाकर तथा उसका कार्यभार श्री अमित शाह को सौंपकर इस क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। उन्होंने आनंद व्यक्त किया कि आज लगभग 94 प्रतिशत राशि सीधे पशुपालक बहनों के बैंक खातों में जमा होती है, जो आर्थिक समृद्धि का उत्तम उदाहरण है।

कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रिमोट से 'अमूल एआई' (Amul AI) डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। इसके बाद सभी ने 'अमूल एआई' की लघु फिल्म देखी।

इससे पहले अमूल परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन पर अमूल के निदेशक मंडल द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अमूल के अध्यक्ष ने सबका स्वागत करते हुए 'अमूल एआई' के बारे में जानकारी दी। अमूल के प्रबंध निदेशक श्री जयन मेहता ने प्रासंगिक संबोधन किया। 'अमूल एआई' ऐप बनाने वाले डॉ. शंकर ने ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अमूल के उपाध्यक्ष श्री गोरधनभाई धामेलिया ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में सांसद श्री मीतेशभाई पटेल, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, प्रधान सचिव श्री अरुणकुमार सोलंकी, जीएसएमएमएफ के पदाधिकारी, अमूल निदेशक मंडल के सदस्य, विधायक सर्वश्री योगेशभाई पटेल, चिरागभाई पटेल, विपुलभाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हसमुखभाई पटेल, अग्रणी श्री संजयभाई पटेल सहित पशुपालक महिलाएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

राजकोट और लालकुआं के बीच चलायी जाएगी स्पेशल ट्रेन,टिकटों की बुकिंग 13 फरवरी से

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराये पर राजकोट और लालकुआं के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 05046/05045 राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 05046 राजकोट-लालकुआं स्पेशल प्रत्येक सोमवार को राजकोट से 22.30 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 05.15 बजे लालकुआं पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 मार्च, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक चलेगी।

इसी तरह, ट्रेन संख्या 05045 लालकुआं-राजकोट स्पेशल प्रत्येक रविवार को लालकुआं से 12.35 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 18.10 बजे राजकोट पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 मार्च, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, पाटन, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचमन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, भरतपुर, मथुरा, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, सोरों शुकर, बदायूँ, बरेली, बरेली सिटी, इज्जतनगर, भोजीपुरा, बहेरी और किच्छा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, सेकंड स्लीपर और जनरल क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 05046 की बुकिंग 13 फरवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रांदेर की रात और जागरूकता का सबक

(जीएनएस)। सूरत के रांदेर इलाके में घटी एक अनोखी चोरी की घटना ने शहरवासियों को चौंका दिया। आमतौर पर चोरी की वारदातों में नकदी, गहने या इलेक्ट्रॉनिक सामान को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार चोर की नजर महंगे ब्रांडेड जूते-चप्पलों पर थी। यह घटना न केवल असामान्य है, बल्कि शहरी जीवन की बदलती प्रवृत्तियों और सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही को भी उजागर करती है। रांदेर नवयुग कॉलेज के पास स्थित डिस्ट्रिक्ट पंचायत सोसाइटी में एक ही रात में 48 घरों के बाहर से फुटवियर चोरी हो जाना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है।

जानकारी के अनुसार, 9 तारीख की देर रात लगभग 2:30 बजे एक अज्ञात युवक सोसाइटी के पीछे की फेंस कूदकर अंदर दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि वह अपने साथ एक खाली बैग लेकर आया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह पहले से योजना बनाकर पहुंचा था। सोसाइटी में लगभग 60 मकान हैं, और चोर ने व्यवस्थित तरीके से एक-एक घर के बाहर रखे जूतों के रैक और बॉक्स की जांच की। यह पूरी घटना करीब एक घंटे तक चलती रही, जिसमें उसने दो बड़े बैग महंगे जूतों से भर लिए और बिना किसी शोर-शराबे के फरार हो गया।

सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह रहा कि चोर ने केवल ब्रांडेड, नए और महंगे दिखने वाले जूते-चप्पल ही उठाए, जबकि साधारण या पुराने फुटवियर को वहीं छोड़ दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उसे बाजार में इन वस्तुओं की संभावित कीमत और मांग का अंदाजा था। संभव है कि चोरी किए गए जूतों को सेकेंड-हैंड बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की योजना रही हो। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि अब अपराधी भी बदलते उपभोक्ता रुझानों और ब्रांड वैल्यू को समझने लगे हैं। घटना की जानकारी सुबह तब सामने आई, जब सोसाइटी के निवासी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकले। दरवाजे के बाहर रखे जूते गायब देखकर लोग हैरान रह गए। कई परिवारों के लिए यह सिर्फ सामान की चोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से यह घटना शहरभर में चर्चा का विषय बन गई।

हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोसाइटी के निवासियों में रोष स्पष्ट है। उन्होंने फुटेज साझा कर अन्य सोसाइटी और अपार्टमेंट के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। यह पहल सामुदायिक जागरूकता का सकारात्मक उदाहरण है, क्योंकि कई बार छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है।

सेवा, समर्पण और संस्कारों से संवरती शिक्षा साधना

(जीएनएस)। वडोदरा की पावन धरती पर जब 'प्रशस्त 2.0' स्क्रीनिंग ऐप के प्रशिक्षण और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार विषयक कार्यशाला का आयोजन हुआ, तो वह केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम भर नहीं था, बल्कि शिक्षा साधना का एक ऐसा आध्यात्मिक संगम बन गया, जहाँ सेवा, समर्पण और संस्कारों की त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित होती दिखाई दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरगृह में एकत्रित हुए जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक केवल अधिकारी नहीं थे, वे ज्ञान-दीप के ऐसे साधक थे, जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन में प्रकाश भरने का संकल्प लेकर उपस्थित हुए थे।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा केवल पुस्तकों और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि यह राष्ट्रनिर्माण की एक पवित्र तपस्या है। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. एम. आई. जोशी का उद्बोधन मानो गुरु-वाणी की तरह उपस्थित जनों के हृदय में उतरता चला गया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को केवल परीक्षा परिणामों या अंकों की सीमा में बाँधने से इंकार करते हुए कहा कि वास्तविक शिक्षा वह है, जो बालक के भीतर नैतिकता, करुणा, अनुशासन और समर्पण के बीज रोपे। उनके शब्दों में एक अनुभवी शिक्षक का तप, त्याग और अनुभव झलक रहा था। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से आत्ममंथन करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, यहाँ अहंकार, मतभेद या मनभेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब शिक्षक स्वयं को सेवक मानकर कार्य करता है, तभी वह बालक के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। उनका यह संदेश किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक साधना मंत्र की तरह था, जिसने उपस्थित शिक्षकों को अपने दायित्व का गहन बोध कराया।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने बदलते शैक्षणिक परिवेश में प्रधानाध्यापक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज का प्रधानाध्यापक केवल प्रशासनिक प्रमुख नहीं, बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक, प्रेरक और पथप्रदर्शक है। विद्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि संस्कारों की कार्यशाला है, जहाँ प्रत्येक बालक एक अनगढ़ शिला की तरह आता है और शिक्षक की छेनी से तराशकर एक सुन्दर मूर्ति में परिवर्तित होता है। उन्होंने कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में नवाचार अपनाने, कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने और स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह संदेश स्पष्ट था कि यदि हम शिक्षा को जीवंत और परिणामोन्मुखी बनाना चाहते हैं, तो हमें पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर सृजनात्मकता और नवाचार का मार्ग अपनाना होगा।

'प्रशस्त 2.0' ऐप का प्रशिक्षण केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि शिक्षा को अधिक सशक्त और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐप विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करने का माध्यम बनेगा। जब किसी बालक की कठिनाइयों को प्रारंभिक स्तर पर ही समझ लिया जाता है, तो उसका समाधान सरल हो जाता है। यह पहल उस करुणा और सजगता का प्रतीक है, जो एक सच्चे शिक्षक के हृदय में होनी चाहिए। तकनीक का यह समावेश तभी सार्थक है, जब उसके पीछे सेवा भाव और संवेदनशीलता हो।

आईसीडीएस कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनवाड़ी और बाल पोषण को बुनियादी शिक्षा से जोड़ते हुए स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। वास्तव में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि बालक कुपोषित है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो शिक्षा का प्रकाश उसके भीतर पूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से पोषण और शिक्षा का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यह विचार भारतीय संस्कृति के उस सिद्धांत को भी पुष्ट करता है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सर्वोपरि माना गया है।

मीता जोशी ने विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्तियों का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उन बालकों के सपनों को पंख देने का माध्यम है, जो संसाधनों के अभाव में अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जब प्रशासन और शिक्षक मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित न रहे, तब शिक्षा वास्तव में समावेशी और न्यायपूर्ण बनती है। यह भावना ही शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन बनाती है।

कार्यक्रम में उपस्थित वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. विपुलभाई भारतीय, शैक्षणिक संघ के पदाधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, बीआरसी एवं सीआरसी समन्वयक और जिले के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस बात के प्रतीक थे कि शिक्षा एक सामूहिक साधना है। यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि एक समर्पित समुदाय का प्रयास है। जब सभी मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो परिणाम अवश्य ही सकारात्मक और प्रभावशाली होते हैं।

इस पूरे आयोजन का सबसे प्रेरक पक्ष यह रहा कि इसमें शिक्षा को केवल पेशा नहीं, बल्कि पूजा के रूप में देखने का संदेश निहित था। भारतीय परंपरा में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान सम्मान दिया गया है। गुरु ही सृजन करता है, गुरु ही संरक्षण करता है और गुरु ही अज्ञान का संहार करता है। ऐसे में जब शिक्षक अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तो विद्यालय मंदिर बन जाता है और कक्षा-कक्ष पूजा-स्थल। प्रत्येक पाठ, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक प्रेरणा एक आरती की तरह बन जाती है, जो बालक के जीवन में प्रकाश भरती है।

महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर 04 जोड़ी "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेनों का संचालन

(जीएनएस)। महाशिवरात्रि मेला के दौरान होने वाली अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराये पर "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन विशेष ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

1. राजकोट–वेरावल–राजकोट अनारक्षित दैनिक स्पेशल (09513/09514)

ट्रेन संख्या 09513 राजकोट–वेरावल स्पेशल प्रतिदिन सुबह 06.55 बजे राजकोट से प्रस्थान कर उसी दिन सुबह 10.55 बजे वेरावल पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09514 वेरावल–राजकोट स्पेशल वेरावल से दोपहर 15.20 बजे प्रस्थान कर रात्रि 20.00 बजे राजकोट पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, वीरपुर, गोंडल एवं भक्तिनगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक संचालित रहेगी।

2. भावनगर टर्मिनस–वेरावल–भावनगर टर्मिनस अनारक्षित दैनिक स्पेशल (09582/09581)

ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल वेरावल से सुबह 06.50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14.00 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09582 भावनगर टर्मिनस–वेरावल स्पेशल भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14.50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 21.35 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, जेतपुर, कुंकावाव, लाठी, ढसा, धोला, सिहोर

एवं भावनगर परा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक चलेगी।

3. वेरावल–गांधीग्राम–वेरावल अनारक्षित दैनिक स्पेशल (09584/09583)

ट्रेन संख्या 09584 वेरावल–गांधीग्राम स्पेशल वेरावल से प्रातः 04.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12.00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09583 गांधीग्राम–वेरावल स्पेशल गांधीग्राम से दोपहर 13.00 बजे प्रस्थान कर रात्रि 21.00 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, जेतपुर, कुंकावाव, लाठी, ढसा, धोला, बोटाद, धंधुका, धोलका एवं बावला स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक संचालित की जाएगी।

4. वेरावल–जूनागढ़–वेरावल मीटरगेज अनारक्षित दैनिक स्पेशल (09591/09592)

ट्रेन संख्या 09591 वेरावल–जूनागढ़ मीटरगेज स्पेशल वेरावल से सुबह 09.15 बजे प्रस्थान कर दोपहर 13.00 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09592 जूनागढ़–वेरावल मीटरगेज स्पेशल जूनागढ़ से दोपहर 13.25 बजे प्रस्थान कर शाम 17.05 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सवनी, तालाला जं., चित्रावड, सासण गीर, कांसियानेस, सताधार, विसावदर, जूनीचावंड, बिलखा एवं तोरणिया स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक संचालित रहेगी। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय-सारिणी की पुष्टि कर लें, रेलवे द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करें तथा स्टेशन एवं ट्रेनों में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में रेलवे का सहयोग करें।

गांधीधाम क्षेत्र से उत्तरी भारत के लिए टिंबर के रेल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु बैठक आयोजित

(जीएनएस)। गांधीधाम में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) के प्रतिनिधियों एवं रेल अधिकारियों के बीच गांधीधाम क्षेत्र से दिल्ली तथा अन्य उत्तरी क्षेत्रों के लिए टिंबर (Timber) के रेल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. जेनिया गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनू त्यागी, गांधीधाम के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक (ARM) श्री आशीष धानिया सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) के प्रतिनिधियों तथा कांडला टिम्बर एसोसिएशन के नौ सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य टिंबर के परिवहन को सड़क मार्ग से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। चर्चा के दौरान यह उल्लेख किया गया कि गांधीधाम क्षेत्र में लगभग 750 आरा मिलें (सॉ मिल्स) हैं, इसके बावजूद रेल मार्ग से टिंबर का परिवहन अभी बहुत कम है।

बैठक में रेल आधारित टिंबर लोडिंग को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स समन्वय को सुदृढ़ करने तथा परिचालन संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

सभी प्रतिभागियों ने टिंबर के रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रेल मार्ग से लकड़ी का अधिक परिवहन होने से लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि, सड़कों पर भीड़भाड़ में कमी तथा पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

ज्ञानदीप प्रज्वलित करेगा लिंबायत का नवयुग

(जीएनएस)। सूरत की पुण्यभूमि पर शिक्षा का एक नया सूर्य उदित होने जा रहा है। लिंबायत और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समाचार केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और उज्ज्वल भविष्य का शुभ संदेश है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लिंबायत क्षेत्र में सरकारी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव उस संकल्प का प्रतीक है, जिसमें शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी सेवा और राष्ट्रनिर्माण का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। यह निर्णय उन हजारों परिवारों के सपनों को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने को विवश होते रहे हैं। टीपी नंबर 69 (गोडादरा-डिंडोली) स्थित 'डिस्ट्रिक्ट सेंटर' के लिए

म्युनिसिपैलिटी को आवंटित अंतिम ब्लॉक नंबर 189 में से लगभग 31,415 वर्गमीटर भूमि सरकारी कॉलेज के लिए समर्पित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भूमि अब केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं रहेगी, बल्कि यह ज्ञान, परिश्रम और सपनों की धरा बनेगी। जब इसी धरती पर पुस्तकालयों की शांति गूंजेगी, प्रयोगशालाओं में विज्ञान के प्रयोग होंगे और कक्षाओं में अध्यापन की पवित्र ध्वनि सुनाई देगी, तब यह भूमि सचमुच तपोभूमि का स्वरूप धारण कर लेगी।

इस योजना के अंतर्गत यह जमीन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी और इसके बदले राज्य सरकार अन्य स्थानों पर उपलब्ध अनुपयोगी सरकारी जमीन आपसी विनिमय के आधार पर म्युनिसिपैलिटी को आवंटित करेगी। शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाना इस बात का प्रमाण है कि शासन भी शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दे रहा है। जब प्रशासन और समाज एक साथ शिक्षा के लिए संकल्पित होते हैं, तब विकास की गति और भी सशक्त हो जाती है।

आर्थिक दृष्टि से भी यह निर्णय सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमेटी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार कॉलेज निर्माण के लिए दी जा रही भूमि का मूल्य 74,800 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। इस आधार पर कुल मूल्य लगभग 234.98 करोड़ रुपये आँका गया है। यह आंकड़ा केवल धनराशि नहीं दर्शाता, बल्कि यह उस निवेश का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में किया जा रहा है। शिक्षा में लगाया गया प्रत्येक रुपया समाज के विकास में कई गुना होकर लौटता है।

इसके बदले राज्य सरकार टी.पी. स्कीम नंबर 79 (सुल्तानाबाद-भीमपोर), टी.पी. स्कीम नंबर 50 (भाठा-बेट) और बामरोली क्षेत्र में स्थित जमीन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार भूमि विनिमय की यह प्रक्रिया संतुलित और न्यायसंगत रूप में आगे बढ़ेगी। परियोजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए एसएमसी, कलेक्टर कार्यालय और संबंधित सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। यह समझौता केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह शिक्षा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण बनेगा।

समझौते से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कानूनी शुल्क सहित लगभग 2.60 करोड़ रुपये का व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी इस बात का संकेत है कि शासन इस परियोजना को गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ा रहा है। जब प्रशासनिक प्रक्रियाएँ स्पष्ट और व्यवस्थित होती हैं, तो विकास कार्यों में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ते हैं।

लोकसभा में तीखी नोकझोंक के बीच राहुल पर विशेषाधिकार नोटिस की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के मौजूदा सत्र में सियासी तापमान उस समय और बढ़ गया जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने लोकसभा में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया भाषण पर कड़ा ऐतराज जताया। रिजीजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने कथित रूप से 'एप्सटीन फाइल' से जुड़े मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर आरोप लगाए, जिन्हें सत्तारूढ़ पक्ष ने पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। सदन में बोलते हुए किरण रिजीजू ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण तथ्यों से परे था और उसमें कई ऐसे दावे किए गए जिनका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन बयानों को गंभीरता से लेती है और ऐसे आरोपों को सदन की गरिमा के खिलाफ मानती है। रिजीजू के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है कि वे तथ्यों के आधार पर बात रखें और यदि कोई आरोप लगाते हैं तो उसके समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करें। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिना प्रमाण के केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए, जो संसदीय परंपराओं के विपरीत है। रिजीजू ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन

अब सदन में राहुल गांधी के कथनों का प्रमाणीकरण मांगेगा। यदि आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो भाजपा उन टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग करेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाकर इस मामले को औपचारिक रूप से उठाया जाएगा, ताकि सदन की गरिमा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए सनसनीखेज आरोपों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार ऐसे बयान देना, जिनका तथ्यात्मक आधार संदिग्ध हो, लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। रिजीजू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का भाषण देने के बाद सदन से चले जाना संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उनके अनुसार, जब किसी सदस्य के वक्तव्य पर सवाल उठते हैं या जवाब दिया जाता है, तो उस सदस्य को सदन में उपस्थित रहकर उसे सुनना और स्पष्टीकरण देना चाहिए।

उन्होंने यह आरोप दोहराया कि कांग्रेस नेता कई बार जानबूझकर विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा देते हैं और फिर चर्चा या जवाब से बचने के लिए सदन से बाहर चले जाते हैं। रिजीजू ने इसे संसदीय नियमों और परंपराओं के प्रति असम्मान बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति से अधिक जिम्मेदारी और गंभीरता की अपेक्षा की जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने सदन के भीतर तीखी नोकझोंक का माहौल बना दिया। विपक्षी दलों ने भाजपा के रुख को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष ने इसे संसदीय शुचिता का प्रश्न बताया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाए जाने की स्थिति में यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जा सकता है, जहां तथ्यों और नियमों के आधार पर इसकी जांच होगी।

विशेषाधिकार हनन का नोटिस तब दिया जाता है जब यह माना जाए कि किसी सांसद ने सदन की गरिमा, अधिकार या विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। यदि समिति को prima facie मामला बनता दिखाई देता है, तो वह संबंधित सदस्य से स्पष्टीकरण मांग सकती है और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय सदन के विवेक पर निर्भर करता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, संसद सत्र के दौरान इस तरह के टकराव आम हैं, लेकिन जब मामला नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हो, तो उसका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। इससे न केवल सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है, बल्कि बाहर भी राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा औपचारिक रूप से नोटिस दाखिल करती है और यदि करती है तो उसका संसदीय प्रक्रिया में क्या परिणाम निकलता है।

फिलहाल, इस विवाद ने एक बार फिर संसद में शिष्टाचार, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर चर्चा को जन्म दिया है। सत्तारूढ़ पक्ष जहां इसे तथ्यहीन आरोपों के खिलाफ आवश्यक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के रूप में देख रहा है। सदन के आगामी दिनों में इस मुद्दे पर और बहस होने की संभावना है, और राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज बनी रहने की उम्मीद है।

सीएमए परीक्षा में सूरत की प्रतिभा का राष्ट्रीय परचम

(जीएनएस)। सूरत। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) द्वारा दिसंबर-2025 में आयोजित सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते ही सूरत शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस बार न केवल सूरत बल्कि पूरे वेस्टर्न इंडिया रीजन (WIRC) के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मेधा और परिश्रम का लोहा मनवाया है। परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूरत शिक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

सीएमए फाइनल परीक्षा में सूरत शहर के चार विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) टॉप-50 में स्थान प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। देशना जैन ने AIR 5 प्राप्त कर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनके साथ पलक अग्रवाल (AIR 17), प्रतीक वालेजा (AIR 30) और हर्ष शाह (AIR 35) ने भी टॉप-50 में स्थान बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन विद्यार्थियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि समर्पण, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ स्थान हासिल किया जा सकता है।

सीएमए सूरत साउथ गुजरात चैप्टर के चेयरमैन सीएमए किशोर वाघेला ने परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 863 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 155 विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप में सफलता प्राप्त की, जबकि 133 विद्यार्थी एक ग्रुप में उत्तीर्ण हुए। वहीं फाइनल परीक्षा में 199 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 48 ने दोनों ग्रुप में और

19 ने एक ग्रुप में सफलता हासिल की। इस प्रकार फाइनल परीक्षा का कुल परिणाम 24 प्रतिशत और इंटरमीडिएट का 18 प्रतिशत दर्ज किया गया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सूरत ने अकेले टॉप-50 में 18 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है।

इंटरमीडिएट परीक्षा में भी सूरत और वेस्टर्न रीजन के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 14 विद्यार्थियों ने टॉप-50 AIR में स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इनमें दीप गजेरा (AIR 5) और लोकेश पाटिल (AIR 6) ने शीर्ष रैंकों में स्थान बनाकर विशेष पहचान बनाई। जिनल कोठारी (AIR 13), भाविन वोरा (AIR 20), अदिति मुंधरा (AIR 24), मुदित जैन (AIR 35), कृष शर्मा (AIR 36), विभूति आढव (AIR 39), श्याम लाहोटी (AIR 40), धवल शियाली (AIR 40), जिनय संघवी (AIR 43), सौरभ पुरोहित (AIR 46), विनायक लुहार (AIR 48) और अंकित पांडव (AIR 49) ने भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इन विद्यार्थियों की उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि शिक्षकों और संस्थान के लिए भी गर्व का विषय है।

वेस्टर्न रीजनल काउंसलर वाइस चेयरमैन सीएमए नितिन शाह ने कहा कि वर्तमान समय में CMA सेक्टर देश का तेजी से उभरता हुआ पेशेवर क्षेत्र है। उद्योग, वित्त, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कॉस्ट अकाउंटेंट्स की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के CMA परिणामों में वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया—जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा शामिल हैं—ने राष्ट्रीय टॉप रैंकों में लगभग एक-तिहाई हिस्सेदारी हासिल की है। यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूरत में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, अनुभवी मेंटर्स और विद्यार्थियों की मेहनत ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां के शैक्षणिक वातावरण ने छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया है। साथ ही, पेशेवर पाठ्यक्रमों के प्रति युवाओं की बढ़ती जागरूकता और समर्पण भी इस उपलब्धि का प्रमुख कारण है।

सूरत में महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क कैंसर जांच अभियान

(जीएनएस)। सूरत। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, गुजरात स्टेट ब्रांच के मार्गदर्शन में सूरत रेड क्रॉस सोसायटी चौर्यासी शाखा तथा गायत्री हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में स्तन कैंसर और गर्भाशय मुख (सर्वाइकल) कैंसर की निःशुल्क जांच हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर जांच, परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करना और प्रारंभिक अवस्था में पहचान सुनिश्चित करना था। चिकित्सकों ने बताया कि यदि स्तन और सर्वाइकल कैंसर का समय पर पता चल जाए तो उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी दृष्टिकोण से यह निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं बिना किसी आर्थिक बाधा के जांच करा सकें। गुजरात रेड क्रॉस सोसायटी के सहयोग से गर्भाशय कैंसर की जांच भी पूरी तरह निःशुल्क की गई। शिविर में उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने महिलाओं को स्तन कैंसर की स्व-जांच (सेल्फ एग्जामिनेशन) की विधि भी समझाई और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कई महिलाओं ने पहली बार इस प्रकार की जांच करवाई और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया, जिससे उनमें आत्मविश्वास और जागरूकता दोनों में वृद्धि देखी गई।

कार्यक्रम में पूर्व मेयर अश्मिताबेन शिरोया, कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, सुमनबेन प्रजापति, दिनेशभाई जोगाणी, लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किशोर मांगरोलिया, जोन चेयरमैन लायन जगदीश बोदरा, डिस्ट्रिक्ट 3232 F2 के चेयरमैन लायन पी.टी. राठौड़ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गायत्री हॉस्पिटल,

रंग अवधूत सोसायटी, माता वाड़ी और लांबे हनुमान रोड क्षेत्र के समाजसेवियों ने भी सेवा सहयोग प्रदान किया। सभी ने इस पहल को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक और सराहनीय बताया।

इस अवसर पर डॉ. पूर्वी मालवीया शिरोया ने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के लंबे समय तक रहने वाले संक्रमण के कारण होता है, जो एक यौन संचारित वायरस है। उन्होंने समझाया कि प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, इसलिए नियमित जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण के माध्यम से इस बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

डॉ. पूर्वी ने यह भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर के सामान्य लक्षणों में असामान्य योनि रक्तस्राव, शारीरिक संबंध के बाद रक्तस्राव, पेल्विक क्षेत्र में दर्द और असामान्य डिस्चार्ज शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे पाप स्मीयर (Pap Smear) जांच समय-समय पर अवश्य करवाएं, क्योंकि यह जांच प्रारंभिक स्तर पर असामान्य कोशिकाओं की पहचान कर सकती है और समय रहते उपचार संभव बनाती है।

डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने अपने संबोधन में कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, गुजरात के चेयरमैन अजयभाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण राज्यभर में रेड क्रॉस विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि संस्था केवल कैंसर जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लड बैंक, आर्टिफिशियल लिंब सेंटर, डेंटल क्लिनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड प्रशिक्षण तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जैसी अनेक सेवाएं भी संचालित कर रही है। इन सेवाओं के माध्यम से हजारों जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है।

शिविर के दौरान महिलाओं को पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली, तनाव और असंतुलित आहार के कारण कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में जागरूकता और समय पर जांच ही सबसे प्रभावी उपाय है।

चौक बाजार में ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू, सूरत मेट्रो टनलिंग पूरी

(जीएनएस)। सूरत। डायमंड सिटी सूरत में मेट्रो रेल परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण और तकनीकी दृष्टि से जटिल चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। शहर के अत्यंत व्यस्त, घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक चौक बाजार क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने अपना लक्ष्य हासिल करते हुए 6.40 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस उपलब्धि को सूरत मेट्रो परियोजना के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह कार्य शहर के सबसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले हिस्से में बिना किसी बड़े हादसे के संपन्न हुआ। कपोदरा और चौक बाजार के बीच डाउन लाइन की 6.40 किलोमीटर लंबी टनल का कार्य लगभग छह महीने पहले ही पूरा कर लिया गया था। अब अप लाइन की टनलिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसके साथ ही इस पूरे अंडरग्राउंड खंड में खुदाई और सुरंग निर्माण का कार्य संपन्न हो गया है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि इंजीनियरिंग दक्षता, सटीक योजना और अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग का

परिणाम है। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (GMRC) ने सूरत रेलवे स्टेशन से चौक बाजार तक लगभग 3.56 किलोमीटर लंबे भूमिगत सेक्शन का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में प्रारंभ किया था। यह क्षेत्र अपनी संकरी गलियों, पुरानी और जर्जर इमारतों तथा घनी आबादी के लिए जाना जाता है। ऐसे इलाके में भूमिगत सुरंग बनाना तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। जमीन के भीतर विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पुराने ढांचों की नींव और भूमिगत संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए टनलिंग की गई।

टनल बोरिंग मशीन को जमीन से लगभग 12 मीटर की गहराई पर संचालित किया गया। निर्माण के दौरान कंपन और ध्वनि के प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए थे। आसपास की इमारतों में सेंसर लगाए गए, जो कंपन के स्तर की लगातार निगरानी करते रहे। किसी भी प्रकार की असामान्य हलचल पर तुरंत कार्रवाई के लिए इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम चौबीसों घंटे तैनात रही।

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील और जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को एहतियातन अस्थायी रूप से होटलों में ठहराया गया। स्थानीय निवासियों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया गया ताकि उन्हें परियोजना की प्रगति और सुरक्षा उपायों की जानकारी मिलती रहे। इस समन्वित प्रयास के कारण पूरे निर्माण कार्य के दौरान किसी बड़े हादसे या संरचनात्मक क्षति की सूचना नहीं मिली। इसे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग सफलता माना जा रहा है।

GMRC अधिकारियों के अनुसार, अब जब टनलिंग कार्य पूरा हो चुका है, तो अगला चरण चौक बाजार स्टेशन और अन्य भूमिगत स्टेशनों पर फिनिशिंग वर्क, ट्रैक बिछाने, विद्युतिकरण और विभिन्न सिस्टम इंस्टॉलेशन का है। सिग्नलिंग, वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी और यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य यह है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी परीक्षण और ट्रायल रन पूरे कर लिए जाएं। सूरत मेट्रो परियोजना का पहला चरण, जिसे कॉरिडोर-1 (सरथाना से ड्रीम सिटी) के नाम से जाना जाता है, जून 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। टनलिंग कार्य की सफल समाप्ति के बाद इस लक्ष्य को लेकर आशावाद और मजबूत हुआ है। परियोजना पूरी होने पर शहर में यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और प्रदूषण में भी गिरावट की उम्मीद है। मेट्रो परियोजना सूरत के शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के कारण शहर में सार्वजनिक परिवहन की मांग लगातार बढ़ रही थी।

गोवा में विशेष पुनरीक्षण के बाद 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को जानकारी दी कि गोवा में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची अब 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले आयोग ने इसे 14 फरवरी को जारी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से तिथि में संशोधन किया गया है। आयोग का कहना है कि सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त समय लिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा की मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी। इस मसौदा सूची में राज्य के कुल 11.85 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 10.84 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया था। शेष 1.01 लाख मतदाताओं को पहचान और दस्तावेज सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी है, जिसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में शामिल सभी नाम वैध और अद्यतन हों। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग घर-घर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और आपत्तियों के निपटारे जैसी प्रक्रियाएं अपनाता है। जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए थे या जिनकी जानकारी अधूरी पाई गई थी, उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिन नागरिकों ने नए मतदाता के रूप में आवेदन किया था या नाम में सुधार की मांग की थी, उनके आवेदनों की भी जांच की गई। आयोग ने बताया कि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले सभी दावों और आपत्तियों का विधिवत निपटारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि कर सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र नाम सूची में शामिल न हो।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। पारदर्शी और त्रुटिरहित सूची न केवल चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी मजबूत करती है। आयोग समय-समय पर विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करता है कि नए मतदाता जुड़ें और जिन लोगों का निधन हो गया है या जो स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम उचित प्रक्रिया के बाद हटाए जाएं। गोवा जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में मतदाता सूची की सटीकता विशेष महत्व रखती है। राज्य में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद चुनावी प्रतिस्पर्धा अक्सर कड़ी होती है, ऐसे में हर एक वोट का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए आयोग किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम की पुष्टि अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तैयारी के बाद ही सूची जारी की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। अब सभी की निगाहें 21 फरवरी पर टिकी हैं, जब गोवा की अंतिम मतदाता सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में आगामी चुनावों की तैयारियों को भी और गति मिलने की संभावना है। चुनाव आयोग ने दोहराया है कि उसकी प्राथमिकता स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है, और मतदाता सूची का शुद्धीकरण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सोना वायदा में 2526 रुपये और चांदी वायदा में 14951 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 92 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118348.58 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 22305.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 96041.45 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39740 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2115.82 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17178.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158436 रुपये के भाव पर खूलकर, 159511 रुपये के दिन के उच्च और 157560 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 156803 रुपये के पिछले बंद के सामने 2526 रुपये या 1.61 फीसदी के ऊछाल के साथ 159329 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1092 रुपये या 0.85 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 129556 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 164 रुपये या 1.02 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16220 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 155900 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157499 रुपये और नीचे में 155626 रुपये पर पहुंचकर, 2111 रुपये या 1.36 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 157031 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 158532 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159900 रुपये और नीचे में 158432 रुपये पर पहुंचकर, 157951 रुपये के पिछले बंद के सामने 1689 रुपये या 1.07 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 159640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 257938 रुपये के भाव पर खूलकर, 267699 रुपये के दिन के उच्च और 257938 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252548 रुपये के पिछले बंद के सामने 14951 रुपये या 5.92 फीसदी की तेजी के संग 267499 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 14019 रुपये या 5.39 फीसदी की बढ़त के साथ 273954 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 14114 रुपये या 5.43 फीसदी की तेजी

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 22305.23 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 96041.45 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 17178.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39740 पॉइंट के स्तर पर

के संग 273876 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 3127.67 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 27.7 रुपये या 2.25 फीसदी बढ़कर 1261.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 5.35 रुपये या 1.64 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 331.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 3.85 रुपये या 1.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 315.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.64 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 189.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1981.21 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5844 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5915 रुपये और नीचे में 5828 रुपये पर पहुंचकर, 92 रुपये या 1.59 फीसदी बढ़कर 5892 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 93 रुपये या 1.6 फीसदी की तेजी के संग 5895 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 284 रुपये के भाव पर खूलकर, 286.2 रुपये के दिन के उच्च और 280.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 288.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.2 रुपये या 1.8 फीसदी गिरकर 283.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 5.1 रुपये या 1.77 फीसदी औंधकर 283.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 967.2 रुपये पर खूलकर, 3 रुपये या 0.31 फीसदी घटकर 966 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8836.90 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8341.57 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2376.30 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 266.64 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 13.86 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 470.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 919.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1044.44 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8991 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63467 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31633 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 425100 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 54096 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8810 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19135 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 61588 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20440 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 24399 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 39197 पॉइंट पर खूलकर, 39787 के उच्च और 39197 के नीचले स्तर को छूकर, 680 पॉइंट बढ़कर 39740 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 26.9 रुपये की बढ़त के साथ 159 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.45 रुपये की गिरावट के साथ 19.6 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 36 रुपये की बढ़त के साथ 246 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2401.5 रुपये की बढ़त के साथ 6825 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11.92 रुपये की बढ़त के साथ 20.65 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 78 पैसे के सुधार के साथ 1.29 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 52.1 रुपये की गिरावट के साथ 115.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.15 रुपये की बढ़त के साथ 15.55 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1229 रुपये की गिरावट के साथ 2811 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7137 रुपये की गिरावट के साथ 14016.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.37 रुपये की गिरावट के साथ 9.12 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 277.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 42 पैसे की नरमी के साथ 0.11 रुपये हुआ।